



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2009/आश्विन 8, 1931

No. 563]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2009/ASVINA 8, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 714(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 में आगे और संशोधन करने के प्रयोजन से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 (इसके बाद उक्त नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 में—

(क) उप-नियम (1) में खण्ड (ख) में, प्रथम प्रावधान के बाद, दूसरे और तीसरे प्रावधान के लिए निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

“बशर्ते यह भी कि मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो अपनी अपनी सेवाओं के प्रमुख हैं; को केन्द्र सरकार पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना निलंबित नहीं रखा जाएगा।

बशर्ते यह भी कि जहां राज्य सरकार, सेवा के ऐसे सदस्य को निलंबित करते हुए एक आदेश पारित करती है जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विचारित है, ऐसा आदेश उस तारीख जिस तारीख से सेवा के सदस्य को निलंबित किया जाता है से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने के पहले, अथवा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से केन्द्र सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अगली अवधि 45 दिनों से अधिक न हो, या तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाती है अथवा निलंबन आदेश की पुष्टि केन्द्र सरकार द्वारा कर दी जाती है, तक वैध नहीं होगा”;

(ख) उप-नियम (1क) के बाद निम्नलिखित उप नियम प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(1ख) भ्रष्टाचार को छोड़कर अन्य आरोपों के आधार पर सेवा के सदस्य के निलम्बन की अवधि अधिकतम एक वर्ष की होगी और निलम्बन की तारीख से एक वर्ष के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी और उपयुक्त आदेश जारी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं करने पर निलम्बन आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

बशर्ते कि निलम्बन को केन्द्रीय मंत्रालय समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक वर्ष के बाद भी जारी रखा जा सकता है।

बशर्ते यह भी कि वह अवधि जिसके दौरान अनुशासनिक कार्यवाही, अदालत के आदेश के कारण स्थगित रहती है, को इस एक वर्ष की सीमा से निकाल दिया जाएगा।

(1ग) भ्रष्टाचार के आरोप पर सेवा के सदस्य की निलम्बन अवधि अधिकतम दो वर्ष की होगी और निलम्बन की तारीख से दो वर्ष के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी और उपयुक्त आदेश पारित कर दिया जाएगा, ऐसा न करने पर निलम्बन आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय मंत्रालय समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर निलम्बन को केवल दो वर्ष से अधिक जारी रखा जा सकता है।

बशर्ते यह भी कि वह अवधि जिसके दौरान अनुशासनिक कार्यवाही, अदालत के आदेश के कारण स्थगित रहती है, को इस दो वर्ष की सीमा से निकाल दिया जाएगा।

(1घ) केन्द्रीय मंत्रालय समीक्षा समिति के संचटन और काम-काज और उनके द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया इन नियमों में संलग्न अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट जैसी होगी।”

(ग) उप-नियम (8) में, खण्ड (ग) में, “अनुसूची” शब्द के स्थान पर “अनुसूची 1” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(घ) उप-नियम (8) में, खण्ड (घ) में “उप-नियम (1) के अंतर्गत” कोष्ठक और आंकड़े शब्दों के लिए “इस नियम के अंतर्ग” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में अनुसूची के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और इस तरह क्रमांकित अनुसूची के बाद निम्नलिखित अनुसूची प्रविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची 2

[नियम 3 उप-नियम (1ख), (1ग) और (1घ) देखें]

1. समीक्षा समिति का संघटन :- केन्द्र सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय मंत्रालय समीक्षा समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i)	संबंधित मंत्रालय/विभाग में भारत सरकार का सचिव	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित मंत्रालय में प्रशासनिक कार्यभार देखने वाले अपर सचिव/संयुक्त सचिव	सदस्य
(iii)	संबंधित मंत्रालय/विभाग में कोई अन्य अपर सचिव/संयुक्त सचिव	सदस्य

टिप्पणी: समिति यह आवश्यक समझे तो कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सचिव(कार्मिक) के अनुमोदन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी को नामित कर सकता है ।

2 काम-काज :- सरकार द्वारा किए गए पत्राचार पर जिसमें निश्चित अवधि के बाहर भी निलंबन को बढ़ाने की मांग की गई है, केन्द्र सरकार की समीक्षा समिति भ्रष्टाचार के इतर आरोपों पर निलंबनाधीन अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करेगी ताकि यह पता लगा सके कि क्या निलम्बन को एक वर्ष की सीमा के बाहर जारी रखने के पर्याप्त कारण हैं और भ्रष्टाचार से इतर आरोपों पर निलंबनाधीन अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करेगी ताकि यह पता लगा सके कि क्या निलंबन को दो वर्ष की सीमा के बाहर जारी रखने के पर्याप्त कारण हैं ।

3. प्रक्रिया:- (क) केन्द्रीय मंत्रालय समीक्षा समिति किसी निलंबन को एक वर्ष से अधिक जारी रखने के न्याय संगत का मूल्यांकन करते समय, जहां सेवा का सदस्य भ्रष्टाचार से इतर आरोपों के आधार पर निलंबनाधीन रखा गया है, आरोपों की जांच अथवा अन्वेषण करने वाले प्राधिकारियों से सुसंगत सूचना प्राप्त करके सेवा के सदस्य के विरुद्ध जांच अथवा अन्वेषण की प्रगति को देखेगी;

(ख) केन्द्रीय मंत्रालय समीक्षा समिति किसी निलंबन को दो वर्ष से अधिक जारी रखने के न्याय संगत का मूल्यांकन करते समय, जहां सेवा का सदस्य भ्रष्टाचार से इतर आरोपों के आधार पर निलंबनाधीन रखा गया है, आरोपों की जांच अथवा अन्वेषण करने वाले प्राधिकारियों से सुसंगत सूचना प्राप्त करके सेवा के सदस्य के विरुद्ध जांच अथवा अन्वेषण की प्रगति को देखेगी;

(ग) केन्द्रीय मंत्रालय समीक्षा समिति स्वयं को इस बावत संतुष्ट करेगी कि अनुशासनिक प्राधिकारी के नियंत्रण के बाहर कारणों से विलम्ब हुआ है और अधिकार के निलंबन को रद्द करने से साक्ष्य से छेड़-छाड़ हो सकती है अथवा जांच अथवा अन्वेषण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है;

(घ) केन्द्रीय सरकार समीक्षा समिति केन्द्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी जिसमें वह अपनी सिफारिशों और निलंबन को जारी रखने से संबंधित निष्कर्षों पर पहुंचने वाले कारणों का स्पष्ट उल्लेख करेगी।”

[फा. सं. 11018/3/2004-ए.आई.एस.-III]

हरजोत कौर, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी.—प्रमुख नियम अधिसूचना संख्या 7/15/63-ए.आई.एस.(II) दिनांक 20 मार्च, 1969 द्वारा प्रकाशित किए गए और निम्नवत् संशोधित किए गए :-

- (i) अधिसूचना सं. 12/2/69-अ.भा.से.(III) दिनांक 13.4.71 सा.का.नि.सं. 588 दिनांक 24 अप्रैल, 1971
- (ii) अधिसूचना सं. 13/4/71-अ.भा.से.(III) दिनांक 11 जनवरी, 1972
- (iii) अधिसूचना सं. 31/7/72-अ.भा.से.(III) दिनांक 22 मई, 1972
- (iv) अधिसूचना सं. 6/9/72-अ.भा.से.(III) दिनांक 5 जुलाई, 1975 सा.का.नि.सं. 872 दिनांक 19 जुलाई, 1975
- (v) अधिसूचना सं. 6/9/73-अ.भा.से.(III) दिनांक 26 जुलाई, 1975 सा.का.नि.सं. 985 दिनांक 9 अगस्त, 1975
- (vi) अधिसूचना सं. 6/5/74-अ.भा.से.(III) दिनांक 28 जुलाई, 1975 सा.का.नि.सं. 988 दिनांक 9 अगस्त, 1975
- (vii) अधिसूचना सं. 11018/4/76-अ.भा.से.(III) दिनांक 25 फरवरी, 1977 सा.का.नि.सं. 358 दिनांक 19 मार्च, 1977
- (viii) अधिसूचना सं. 11018/12/76-अ.भा.से.(III) दिनांक 12 जुलाई, 1977 सा.का.नि.सं. 983 दिनांक 30 जुलाई, 1977

- (ix) अधिसूचना सं. 11018/12/77-अ.भा.से.(III) दिनांक 31 मई, 1978
सा.का.नि.सं. 753 दिनांक 17 जून, 1978
- (x) अधिसूचना सं. 11018/6/78-अ.भा.से.(III) दिनांक 16 नवंबर, 1978
सा.का.नि.सं. 1415 दिनांक 2 दिसंबर, 1978
- (xi) अधिसूचना सं. 11018/13/78-अ.भा.से.(III) दिनांक 4 जनवरी, 1979
- (xii) अधिसूचना सं. 11018/11/78-अ.भा.से.(III) दिनांक 16 जून, 1979
- (xiii) अधिसूचना सं. 11018/7/79-अ.भा.से.(III) दिनांक 11 नवंबर, 1980
सा.का.नि.सं. 1220 दिनांक 29 नवंबर, 1980
- (xiv) अधिसूचना सं. 11018/15/78-अ.भा.से.(III) दिनांक 13 अक्टूबर, 1981
सा.का.नि.सं. 959 दिनांक 31 अक्टूबर, 1981
- (xv) अधिसूचना सं. 28013/2/78-अ.भा.से.(III) दिनांक 12 जनवरी, 1982
सा.का.नि.सं. 92 दिनांक 31 जनवरी, 1982
- (xvi) अधिसूचना सं. 11018/18/81-अ.भा.से.(III) दिनांक 3 अगस्त, 1983
सा.का.नि.सं. 612 दिनांक 20 अगस्त, 1983
- (xvii) अधिसूचना सं. 11018/19/81-अ.भा.से.(III) दिनांक 3 फरवरी, 1984
सा.का.नि.सं. 162 दिनांक 18 फरवरी, 1984
- (xviii) अधिसूचना सं. 11018/2/87-अ.भा.से.(III) दिनांक 9 फरवरी, 1988
- (xix) अधिसूचना सं. 11018/7/87-अ.भा.से.(III) दिनांक 26 फरवरी, 1988
- (xx) अधिसूचना सं. 11018/3/97-अ.भा.से.(III) दिनांक 13 जुलाई, 1998
सा.का.नि.सं. 130 दिनांक 25 जुलाई, 1998
- (xxi) अधिसूचना सं. 11018/1/98-अ.भा.से.(III) दिनांक 25 अगस्त, 1998
सा.का.नि.सं. 177 दिनांक 12 सितंबर, 1998
- (xxii) अधिसूचना सं. 11018/3/98-अ.भा.से.(III) दिनांक 1 जून, 2000
सा.का.नि.सं. 212 दिनांक 17 जून, 2000
- (xxiii) अधिसूचना सं. 11018/5/2000-अ.भा.से.(III) दिनांक 4 अप्रैल, 2002
सा.का.नि.सं. 118 दिनांक 13 अप्रैल, 2002
- (xxiv) अधिसूचना सं. 11018/1/2002-अ.भा.से.(III) दिनांक 26 जून, 2003
सा.का.नि.सं. 249 दिनांक 12 जुलाई, 2003

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2009

G.S.R. 714(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the State Governments concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969, namely:-

1. (1) These rules may be called the All India Services (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, -

(a) in sub-rule (1), in clause (b), after the first proviso, for the second and the third proviso, the following provisos shall be substituted, namely : -

“Provided further that the Chief Secretary, Director General of Police and the Principal Chief Conservator of Forests, who are the heads of the respective Services, shall not be placed under suspension without obtaining prior approval of the Central Government:

Provided also that, where a State Government passes an order placing under suspension a member of the Service against whom disciplinary proceedings are contemplated, such an order shall not be valid unless, before the expiry of a period of forty-five days from the date from which the member is placed under suspension, or such further period not exceeding forty-five days as may be specified by the Central Government for reasons to be recorded in writing, either disciplinary proceedings are initiated against him or the order of suspension is confirmed by the Central Government.”;

(b) after sub-rule (1A), the following sub-rules shall be inserted, , namely : -

“(1B) The period of suspension of a member of the Service on charges other than corruption shall not exceed one year and the inquiry shall be completed and appropriate order shall be issued within one year from the date of suspension failing which the suspension order shall automatically stand revoked:

Provided that the suspension can be continued beyond one year only on the recommendations of the Central Ministry's Review Committee:

Provided further that the period during which the disciplinary proceedings remain stayed due to orders of a Court of Law, shall be excluded from this limit of one year.

(1C) The period of suspension of a member of the Service on charges of corruption shall not exceed two years and the inquiry shall be completed and appropriate order shall be issued within two years from the date of suspension failing which the suspension order shall automatically stand revoked:

Provided that the suspension can be continued beyond two years only on the recommendations of the Central Ministry's Review Committee:

Provided further that the period during which the disciplinary proceedings remain stayed due to orders of a Court of Law, shall be excluded from this limit of two years.

(1D) The composition and functions of the Central Ministry's Review Committee and the procedure to be followed by them shall be as specified in Schedule 2 annexed to these rules.”;

(c) in sub-rule (8), in clause (c), for the word “Schedule” the word “Schedule 1” shall be substituted.

(d) in sub-rule (8), in clause (d), for the words bracket and figure “under sub-rule (1)”, the words “under this rule” shall be substituted.

3. In The Schedule to the said rules shall be numbered as Schedule 1 and after Schedule 1, as so numbered, the following Schedule shall be inserted, namely : -

“SCHEDULE 2

[See rule 3 sub-rule (1B), (1C) and (1D)]

1. Composition of the Review Committees.- The Central Ministry's Review Committee constituted by the Central Government: shall consist of -

(i)	Secretary to the Government of India in the concerned Ministry/Department.	Chairperson
(ii)	Additional Secretary/Joint Secretary in charge of Administration in the concerned Ministry	Member
(iii)	Any other Additional Secretary/Joint Secretary in the concerned Ministry/Department.	Member

Note: The Committee may, if considered necessary, co-opt an officer of the Department of Personnel and Training with the approval of Secretary (Personnel), Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

2. Functions.- On a reference being made by the Government that has ordered the suspension seeking extension beyond the period stipulated, the Central Ministry's Review Committee shall review the cases of officers under suspension on charges other than corruption in order to determine whether there are sufficient grounds for continuation of suspension beyond the period of one year and review the cases of officers under suspension on charges of corruption in order to determine whether there are sufficient grounds for continuation of suspension beyond the period of two years.
3. Procedure:- (a) The Central Ministry's Review Committee while assessing the justification for further continuation of any suspension beyond the period of one year, where the member of the Service is placed on suspension on charges other than corruption, shall look into the progress of any enquiry or investigation against the member of the Service by obtaining relevant information from the authorities enquiring or investigating into the charges;
- (b) The Central Ministry's Review Committee while assessing the justification for further continuation of any suspension beyond the period of two years, where the member of the Service is placed on suspension on charges of corruption, shall look into the progress of any enquiry or investigation against the member of the Service by obtaining relevant information from the authorities enquiring or investigating into the charges;
- (c) The Central Ministry's Review Committee shall satisfy itself that the delay has occurred for reasons beyond the control of the disciplinary authority and reinstatement of the officer may result in his tampering with the evidence or otherwise influencing the process of enquiry or investigation;
- (d) The Central Ministry's Review Committee shall submit a detailed report to the Central Government, clearly stating its recommendations and the reasons for arriving at the conclusions relating to the continuance of suspension.”.

[F. No. 11018/3/2004-AIS-III]
HARJOT KAUR, Director (Services)

Note.- The principal rules were published vide Notification No. 7/15/63-AIS (II) dated the 20th March, 1969 and subsequently amended as under:

- i) Notification No. 12/2/69-AIS(III) dated the 13th April, 1971 G.S.R No.588 dated the 24th April, 1971
- ii) Notification No. 13/4/71-AIS(III) dated the 11th January, 1972
- iii) Notification No. 31/7/72-AIS(III) dated the 22nd May, 1972
- iv) Notification No. 6/9/72-AIS(III) dated the 5th July, 1975 G.S.R No.872, dated the 19th July, 1975
- v) Notification No. 6/9/73-AIS(III) dated the 26th July, 1975 G.S.R No.985 dated the 9th August, 1975

- vi) Notification No. 6/5/74-AIS(III) dated the 28th July, 1975 G.S.R No.988 dated the 9th August, 1975
- vii) Notification No. 11018/4/76-AIS(III) dated the 25th February, 1977 G.S.R No.358 dated the 19th Marcy, 1977
- viii) Notification No. 11018/12/76-AIS(III) dated the 12th July, 1977 G.S.R No. 983 dated the 30th July, 1977
- ix) Notification No. 11018/12/77-AIS(III) dated the 31st May, 1978 G.S.R No. 753 dated the 17th June, 1978
- x) Notification No. 11018/6/78-AIS(III) dated the 16th November, 1978 G.S.R No.1415 dated the 2nd December, 1978
- xi) Notification No. 11018/13/78-AIS(III) dated the 4th January, 1979
- xii) Notification No.11018/11/78-AIS(III) dated the 16th June, 1979
- xiii) Notification No. 11018/7/79-AIS(III) dated the 11th November, 1980 G.S.R No.1220 dated the 29th November, 1980
- xiv) Notification No. 11018/15/78-AIS(III) dated the 13th October, 1981 G.S.R No. 959 dated the 31st October, 1981
- xv) Notification No. 28013/2/78-AIS(III) dated the 12th January, 1982 G.S.R No. 92 dated the 31st January, 1982
- xvi) Notification No. 11018/18/81-AIS(III) dated the 3rd August, 1983 G.S.R No. 612 dated 20th August, 1983
- xvii) Notification No. 11018/19/81-AIS(III) dated the 3rd February, 1984 G.S.R No. 162 dated the 18th February, 1984
- xviii) Notification No. 11018/2/87-AIS(III) dated the 9th February, 1988
- xix) Notification No. 11018/7/87-AIS(III) dated the 26th February, 1988
- xx) Notification No. 11018/3/97-AIS(III) dated the 13th July, 1998 G.S.R No. 130 dated the 25th July, 1998
- xxi) Notification No. 11018/1/98-AIS(III) dated the 25th August, 1998 G.S.R No. 177 dated the 12th September, 1998
- xxii) Notification No. 11018/3/98-AIS(III) dated the 1st June, 2000 G.S.R No. 212 dated the 17th June, 2000
- xxiii) Notification No. 11018/5/2000-AIS(III) dated the 4th April, 2002 G.S.R No. 118 dated the 13th April, 2002
- xxiv) Notification No. 11018/1/2002-AIS(III) dated the 26th June, 2003 G.S.R No. 249 dated the 12th July, 2003.

3561 GI/09-3